

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :- 00437 / 2023

बिमला सिहाग

—अपीलार्थी

## बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), झुंझुनू।
4. मुख्य खण्ड शिक्षा अधिकारी, बुहाना, झुंझुनू।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.01.2023

आदेश की दिनांक : 30.01.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप गरसा, अधिवक्ता

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य  
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

## आदेश

1. मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर शहीद सुबेदार मेजर रामपाल सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, काजला, बुहाना, झुंझुनू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक-1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से शहीद जय नारायण राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कुलोठ कलां, झुंझुनू में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है।

अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण 3 महीने की अल्प अवधि में किया गया है तथा अपीलार्थी के स्थान पर किसी को भी पदस्थापित नहीं किया गया है। अपीलार्थी एक विदवा महिला है। उनका स्थानान्तरण असक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है जो अनुचित एवं विधि विरुद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक-1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर शहीद सुबेदार मेजर रामपाल सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, काजला, बुहाना, झुंझुनू में कार्य करने दिया जावे तथा उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन प्रधानाचार्य के पद पर शहीद सुबेदार मेजर रामपाल सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, काजला, बुहाना, झुंझुनू में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी के 3 माहीने में स्थानान्तरण होने का प्रश्न है, प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :

*"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"*

- 5 जहां तक अपीलार्थी के विदवा होते हुए स्थानान्तरण का प्रश्न है चूंकि अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिले के अन्दर ही किया गया है इसप्रकार अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है।
- 6 उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)  
सदस्य

(शुचि शर्मा)  
सदस्य